भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3532
उत्तर देने की तारीख 24.03.2022

कोयले की कमी का एमएसएमई पर प्रभाव

3532. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकीः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास कोयले की कमी के कारण एमएसएमई पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोयले की कमी को दूर करने और एमएसएमई पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई कदम उठाया है या कोई कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक क्या प्रगति हुई है और भविष्य के लिए समय-सीमा और लक्ष्य क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ङ) नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अनुसार, एमएसएमई और 10,000 मीट्रिक टन तक की वार्षिक आवश्यकता वाले अन्य उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्य नामित एजेंसियों (एसएनए) को 8 मिलियन टन कोयला आवंटित करने के लिए चिह्नित किया गया है। राज्यों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला उनके अधिकृत एसएनए को आवंटित किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 13 राज्यों और 18 एसएनए को 6.6743 मिलियन टन कोयले का आवंटन किया है।

*****